



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940

No. 160]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 9 अप्रैल, 2018

**संख्या टीएएमपी/8/2018-वीपीटी.**— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) पर यांत्रिक लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत करने के लिए मैसर्स एसआर विजाग टर्मिनल लिमिटेड से अपने दरमानों की अधिसूचना के बारे में प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/8/2018-वीपीटी

मैसर्स एसआर विजाग टर्मिनल लिमिटेड

...

आवेदक

गणपूर्ति:

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (आर्थिक)

**आदेश**

(अप्रैल, 2018 के 5वें दिन पारित)

मामला, लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) पर वर्तमान बाह्य हार्बर यांत्रिक सुविधा (चरण 1) के उन्नयन के दरमानों की अधिसूचना के लिए मैसर्स एसआर विज्ञाग टर्मिनल लिमिटेड (ईवीटीएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. ईवीटीएल द्वारा अपने 11 जनवरी, 2018 के प्रस्ताव में किये गए निवेदनों पर चर्चा करने से पूर्व, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस प्राधिकरण ने डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के भीतर हार्बर में वैस्ट-क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू 1) बर्थ पर लौह अयस्क प्रहस्तन के यांत्रिक प्रहस्तन के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश, 2008 के अंतर्गत वीपीटी द्वारा दायर अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण प्रस्ताव के आधार पर 29 नवंबर, 2010 को आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी पारित किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 30 दिसम्बर, 2010 के राजपत्र संख्या 347 में अधिसूचित किया गया था।

3.1. ईवीटीएल ने अपने 11 जनवरी, 2018 के पत्र के द्वारा इस प्राधिकरण को अनुरोध किया है कि दरमान उसके नाम से अधिसूचित किये जाएं। ईवीटीएल द्वारा उठाये गए मुख्य मुद्दों का सारांश निम्नवत है:-

(i) ईवीटीएल ने डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के माध्यम से बाह्य हार्बर यांत्रिक सुविधा का चरण-1 का कार्यभार 14 मई 2015 से संभाल लिया है और 31 दिसंबर, 2017 को 98% परियोजना कार्य पूरा कर लिया है। वर्तमान, परिदृश्य में ईवीटीएल परियोजना के चरण-1 को 28 फरवरी, 2018 तक पूरा कर लेगा।

(ii) उक्त संदर्भ में, ईवीटीएल ने महापत्तन न्यास वीपीटी परियोजनाओं की स्थापना का अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश, 2008 के अनुरूप चरण- 1, परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, “संशोधित कार्गो प्रहस्तन प्रशुल्क”, की प्रयोज्यनीयता की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

(iii) वीपीटी पर लौह अयस्क के यांत्रिक प्रहस्तन के अधिकतम प्रशुल्क का निर्धारण 29 नवंबर, 2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा नवंबर 2010 में किया गया था, जो इस प्रकार है:

(क) कार्गो प्रहस्तन प्रभार— 110.67 रु. प्रति मीट्रिक टन

(ख) 15 दिन की निशुल्क अवधि के पश्चात् भंडारण प्रभार (रुपये में प्रति टन प्रति दिन या उसके एक भाग पर)

निशुल्क अवधि के पश्चात् शेष कार्गो के लिए पहले सप्ताह की दर	शेष कार्गो पर दूसरे सप्ताह की दर	शेष कार्गो पर तीसरे सप्ताह से दर
<b>0.64</b>	<b>1.28</b>	<b>2.56</b>

(ग) विविध प्रभार: – 1.13 रु. प्रति टन या उसके एक भाग पर

(iv) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत अपफ्रंट प्रशुल्क नियतन के मामलों के लिए सूचकांकित प्रशुल्क कैप्स निकालने के लिए सूचकांकन कारक संबंधी प्राधिकरण के परिपत्र के संदर्भ में, “संशोधित कार्गो प्रहस्तन प्रशुल्क” वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए परियोजना समापन की तारीख से 25.67% वृद्धि कारक पर सुविचार करते हुए नीचे दर्शाया गया है:-

(क) कार्गो प्रहस्तन प्रभार – 139.08 रु. प्रति मीट्रिक टन

(ख) भंडारण प्रभार (रुपये में प्रति टन प्रति दिन या उसके एक भाग पर)

निशुल्क अवधि के पश्चात् शेष कार्गो के लिए पहले सप्ताह की दर	शेष कार्गो पर दूसरे सप्ताह की दर	शेष कार्गो पर तीसरे सप्ताह से दर
0.84	1.61	3.22

(ग) विविध प्रभार – 1.42 रु. प्रति टन या उसके एक भाग

[डब्ल्यूपीआई वृद्धि का 60% लागू करने के लिए दरमान की सामान्य टिप्पणी में आधार वर्ष 01 जनवरी, 2010 निर्धारित है।]

3.2. ईवीटीएल ने तुरंत संदर्भ के लिए वीपीटी और ईवीटीएल के बीच हुए रियायत करार (सीए) का प्रशुल्क परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया है और अनुरोध किया है दरमान संशोधन की विधिवत् समीक्षा की जाए और महापत्तन न्यास अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अधिसूचित किया जाए।

4.1. ईवीटीएल का प्रस्ताव चरण-1 परियोजना के, अर्थात् बाह्य हार्बर पर लौह अयस्क प्रहस्तन यांत्रिक सुविधा का उन्नयन, सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.9.1. के हवाले से उसके नाम से दरमानों की अधिसूचना जारी करने के संबंध में है।

4.2. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि इसके दरमानों की अधिसूचना के लिए ईवीटीएल के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न नहीं हैं:-

- हर प्रकार से पूरे, उसकी सोपाधिकताओं सहित, प्रस्तावित दरमान।
- स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी समापन प्रमाणपत्र की प्रति।

4.3. तदनुसार, ईवीटीएल के हमारे 2 फरवरी, 2018 के पत्र के द्वारा वांछित दस्तावेज़/सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। ईवीटीएल को यह भी अनुरोध किया गया कि वह प्रस्तावित दरमानों की एक प्रति वीपीटी की टिप्पणियों के लिए वीपीटी को भी भेजे। इसके पश्चात् 28 फरवरी, 2018 और 9 मार्च, 2018 को अनुस्मारक भी भेजे गए।

5.1. वीपीटी को, ग्राही पत्तन होने के नाते, हमारे 2 फरवरी 2018 के पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया था कि वह कुछ मुद्दों पर सूचना/स्पष्टीकरण भेजे। वीपीटी को एक स्वतंत्र अभियंता से समापन प्रमाणपत्र की प्रति भेजने और ईवीटीएल से सोपाधिकताओं के साथ प्रस्तावित प्रारूप दरमानों के प्राप्त होने पर अपनी टिप्पणियां भी यथाशीघ्र भेजे।

5.2. हमारे 2 फरवरी 2018 के पत्र और 28 फरवरी 2018 के अनुस्मारक के संदर्भ में, वीपीटी ने अपने 07 मार्च, 2016 के पत्र के साथ अपना उत्तर भेजा। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेज़/टिप्पणियों और वीपीटी द्वारा दिया गया उत्तर निम्नवत् है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	वीपीटी की सूचना/स्पष्टीकरण
1.	लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए वीपीटी के भीतरी हार्बर में डब्ल्यूक्यू-1 बर्थ के यांत्रिकीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क वीपीटी द्वारा 275.20 करोड़ रु. की कुल आकलित पूंजीगत लागत के साथ वीपीटी द्वारा संकल्पित परियोजना सुविधा के लिए है, जैसा उक्त आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 से देखा जा सकता है। अब ईवीटीएल ने इस परियोजना के चरण-1 के दरमानों की अधिसूचना का प्रस्ताव किया है। वीपीटी और ईवीटीएल के बीच 13 दिसंबर, 2013 को हुए रियायत करार से पता चलता है कि चरण-1 वर्तमान यांत्रिकीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के उन्नयन के लिए है और इसमें इस	(क) लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए “बाह्य हार्बर में वर्तमान सुविधा का उन्नयन और भीतरी हार्बर में नई सुविधा का विकास” की परियोजना कुल 845.41 करोड़ रु. की आकलित लागत पर डीबीएफओटी आधार पर 14 मई, 2015 को मैसर्स एसआर विजाग टर्मिनल लिमिटेड को दी गई थी। परियोजना के विकास की संकल्पना दो चरणों में की गई थी।  (ii) चरण-1: बाहरी हार्बर में वर्तमान मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा का 395.02 करोड़ रु. की आरंभिक आकलित लागत पर उन्नयन और वर्तमान सिविल ढांचे के साथ संयंत्र, मशीनरी के मूल्य के लिए एक बारगी 185.87

<p>परियोजना के लिए संकल्पित पूर्ण पूंजीगत निवेश नहीं होता जिसके लिए अप्रकंट प्रशुल्क चाहा गया और अनुमोदित किया गया था। रियायत करार के पृष्ठ 120-129 पर परिशिष्ट - 4 से यह पता चलता है कि अप्रकंट प्रशुल्क का अनुमोदन चाहते समय उपस्करों में अधिकतर निवेश, जिनको वीपीटी द्वारा परियोजना लागत में आकलित किया गया था। चरण-II में लगाया जाना संकल्पित है। वीपीटी, ग्राही पत्तन होने के नाते, परियोजना के चरण-1 के दरमानों में उपयुक्त घटौती के प्रस्ताव पर सुविचार करे ताकि यह प्राधिकरण चरण-1 के दरमान अधिसूचित करने में सक्षम हो सके। यह दरमान स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी समापन प्रमाणपत्र के अधीन होंगे।</p> <p>प्रसंगवश, इसी प्रकार के मामले में, वीओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) ने प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत शासित एक वीओटी प्रचालक के नाम में सूचकांकित अप्रकंट दरमानों की अधिसूचना के प्रस्ताव का संसाधन करते समय, कन्वेयर सुविधा के पूरा होने तक और प्रचालक द्वारा पूरी तरह से प्रचालन आरंभ किये जाने तक स्वतः ही दरमानों में घटौती का प्रस्ताव किया था।</p>	<p>करोड़ रु. के अप्रकंट प्रशुल्क पर किया जाना जिसका ग्राही द्वारा रियायती प्राधिकारी को भुगतान किया जायेगा।</p> <p>(ii) चरण-II: भीतरी हार्बर में 12.5 मिलियन टन बाहरी हार्बर पर या 2 मिलियन टन भीतरी हार्बर पर, जो भी पहले हो, प्राप्त कर पर 26.52 करोड़ रु. की आकलित लागत पर नई सुविधा का विकास करना।</p> <p>(ख) रियायत करार का परिशिष्ट-4(घ) बताता है कि “यदि रियायत देने की तारीख से तीन (3) वर्ष के भीतर ऊपर खंड (ख) में दी गयी न्यूनतम प्रवाह क्षमता प्राप्त नहीं होती तो ग्राही द्वारा चरण-II निवेश को आरंभ और निष्पादित करने की वचनबद्धता के प्रमाणस्वरूप दी गई प्रस्तुत अतिरिक्त गारंटी (जैसा रियायत करार के अनुच्छेद 4.2 में दिया गया है) लौटा दी जायेगी और रियायत प्राधिकारी को डब्ल्यूक्यू-1 बर्थ के बारे में वैकल्पिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।”</p> <p>(ग) दो चरणों में विकसित की जाने वाली परियोजना के अप्रकंट प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव वीपीटी द्वारा 20.11.2012 के पत्र संख्या आईआरएनपी/एसटीडीएस/आईआर/प्रशुल्क-2012 के द्वारा प्राधिकरण को भेजा गया था। प्राधिकरण ने 7.12.2012 और 31.12.2012 के पत्र संख्या टीएएमपी/77/2012-वीपीटी के द्वारा निम्नलिखित बताया:-</p> <p>(i) वीपीटी पर मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क कैप्स 29.11.2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा नवंबर, 2010 में नियत किये गए थे जिनमें टिवन वैगन टिप्लर, स्टैकर-सह-रीक्लेमर, शिप लोडर, बैल्ट कन्वेयर पे लोडर आदि जैसे उपकरणों से लौह अयस्क के मशीनीकृत प्रहस्तन की संकल्पना की गई थी।</p> <p>(ii) अप्रकंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के अनुसार, निर्धारित प्रशुल्क कैप्स आगामी पांच वर्षों में समरूप कार्गो/सेवा के लिए बाद में बोली लगायी जाने वाली सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, नवंबर 2010 में लौह अयस्क के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए निर्धारित अप्रकंट प्रशुल्क सभी बोली लगायी गई परियोजनाओं के लिए नवंबर, 2015 तक लागू होंगे।</p> <p>(iii) वीपीटी पर लौह अयस्क प्रहस्तन के टैरिफ कैप्स पहले ही 2010 में निर्धारित किये गए और उनकी समीक्षा 2015 में की जानी थी।</p> <p>(iv) अप्रकंट प्रशुल्क दिशानिर्देश सुविधा के चरण-वार विकास के आधार पर अप्रकंट प्रशुल्क निर्धारण अनुबद्ध नहीं करते।</p> <p>(घ) बिंदु (i) में चाही गई सूचना के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान प्रस्ताव में विकास के लिए संकल्पित</p>
---	--

		<p>सुविधाएं, बाहरी हार्बर चरण-1 और भीतरी हार्बर (चरण-2) समान उपस्करों के साथ मशीनीकृत सुविधाएं हैं जैसे ट्रिवन वैगन टिप्लर, स्टैकर-सह-रीक्लेमर, शिप लोडर, बैल्ट कन्वेयर पे लोडर आदि जो वीपीटी के प्रस्ताव में दी गई हैं, जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा 29/11/2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा प्रशुल्क अधिसूचित किया गया था</p> <p>(ड) इस प्रकार, मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के लिए अधिसूचित वही प्रशुल्क, दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.2 के अनुपालन में, वर्तमान परियोजना के लिए भी अपनाया गया है, क्योंकि संकल्पित कार्गो और सेवा वीपीटी के प्रस्ताव के समरूप हैं जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा 29/11/2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा प्रशुल्क अधिसूचित किया गया था और बोली लगाई है।</p> <p>(च) यह भी स्पष्ट करना है कि, बाहरी हार्बर (चरण-1) में सुविधा का स्कोप वर्तमान सुविधा को उन्नयन करने का है जिसमें ट्रिवन टिप्लर, थर्ड टिप्लर, रिसीविंग कन्वेयर स्टैकर, भंडारण यार्ड, बकट व्हील रीक्लेमर, शिपिंग कन्वेयर और शिपलोडर शामिल है। सुग्राही द्वारा 185.87 करोड़ रु. का एक बारगी अपफ्रंट प्रशुल्क वीपीटी को सिविल ढांचे के साथ वर्तमान प्लांट और मशीनरी, लौह अयस्क प्रहस्तन परिसर की भूमि के सिवाय, के मूल्य के रूप में देना होगा जिसे रियायत दाता प्राधिकारी द्वारा रियायत आदेश देने की तारीख से पहले उपलब्ध कराया जायेगा। इस सुविधा को उन्नयन की अनुमानित लागत 395.02 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, चरण-1 में मशीनीकृत सुविधा की कुल आकलित लागत 580.89 करोड़ रु. थी। सुविधा की क्षमता के 12.5 एमटीपीए से बढ़कर 16.2 एमटीपीए होने का अनुमान है।</p> <p>(छ) इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि, चरण-I और चरण-II स्वतंत्र हैं परंतु अंतर निर्भर नहीं है। चरण-I और चरण-II अपनी स्वतंत्र उत्पादकता देते हैं। रियायत करार का परिशिष्ट 4 (घ) स्पष्ट रूप से बताता है कि चरण-II: भीतरी हार्बर में 12.5 मिलियन टन बाहरी हार्बर पर या 2 मिलियन टन भीतरी हार्बर पर, जो भी पहले हो, प्राप्त कर पर 26.52 करोड़ रु की आकलित लागत पर नई सुविधा का विकास करना होगा। यदि रियायत देने की तारीख से तीन (3) वर्ष के भीतर न्यूनतम प्रवाह क्षमता प्राप्त नहीं होती तो ग्राही द्वारा चरण-II निवेश को आरंभ और निष्पादित करने की वचनबद्धता के प्रमाणस्वरूप दी गई प्रस्तुत अतिरिक्त गारंटी (जैसा रियायत करार के अनुच्छेद 4.2 में दिया गया है) लौटानी होगी और रियायत प्राधिकारी को डब्ल्यूक्यू -1 बर्थ के बारे में वैकल्पिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।"</p>
--	--	---

		उपरोक्त को देखते हुए, यह कहा जाता है कि 29.11.2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क को वर्तमान परियोजना के बाहरी हार्बर (चरण-1) में अपनाया जाना यथोचित और युक्तिसंगत है और किसी घटौती की जरूरत नहीं है। इसलिए, सुग्राही द्वारा अनिवार्य अपेक्षाओं के पूरा करने पर बाहरी हार्बर सुविधा (चरण-1) के लिए दरमानों को अधिसूचित करने पर सुविचार करने का अनुरोध किया जाता है।
2.	वीपीटी स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी समापन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।	वीपीटी ने इस बिंदु का उत्तर नहीं दिया।
3.	ईवीटीएल ने परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रारूप दरमान नहीं भेजे हैं। ईवीटीएल को अनुरोध किया जाता है कि वह पूर्ण प्रस्तावित प्रारूप दरमान वीपीटी और साथ ही साथ प्राधिकरण को भी भेजे। ईवीटीएल से प्रस्तावित प्रारूप दरमान की प्राप्ति पर वीपीटी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।	पत्तन द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।  [ईवीटीएल ने अपने 7 मार्च 2018 के पत्र के साथ दरमानों की प्रति वीपीटी को भेजी है और संशोधित दरमान 16 मार्च, 2018 के ई-मेल के द्वारा भेजे हैं।]

6.1. हमारे 02 फरवरी, 2018 के पत्र के प्रत्युत्तर में, ईवीटीएल ने अपने 9 मार्च, 2018 के ई-मेल के द्वारा सामान्य निबंधनों और शर्तों के साथ प्रस्तावित प्रारूप दरमानों की प्रति भेजी है। ईवीटीएल ने प्रस्तावित दरमानों की प्रति वीपीटी को भी पृष्ठांकित की है। ईवीटीएल द्वारा किये गए मुख्य निवेदन इस प्रकार हैं:-

- (i) प्रारूप प्रस्तावित दरमान, सभी निबंधनों और शर्तों, टर्मिनल सूचना; ग्राहक पंजीकरण प्रक्रिया; और संपर्क सूचना के साथ भेजे गए हैं। भाग क में उल्लिखित प्रस्तावित दरें सूचकांकन कारक के संबंध में प्राधिकरण के परिपत्र के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 में परिवर्तन के अधीन है। प्रारूप दरमान की प्रति समीक्षा और टिप्पणी के लिए वीपीटी को भी भेजी जाती है।
- (ii) (क) जहां तक स्वतंत्र अभियंता के समापन प्रमाणपत्र का संबंध है, ईवीटीएल ने बताया है कि अधिकतम परियोजना कार्गो का स्वतंत्र अभियंता द्वारा व्यक्ति रूप से निरीक्षण किया गया है और उसके द्वारा जारी पंच-पवाईट को अधिकतम सीमा तक ठीक भी कर दिया गया है। 28 फरवरी, 2018 को, ईवीटीएल 99.34% परियोजना कार्य पूरा कर सका है।  
(ख) ईवीटीएल यह पूर्वानुमान लगाता है कि स्वतंत्र अभियंता द्वारा एकीकृत जांच मार्च 2018 में की जायेगी जिसके पश्चात् स्वतंत्र अभियंता द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और प्राप्त होते ही उसे आपके साथ साझा किया जायेगा।
- (iii) इस पृष्ठभूमि में, ईवीटीएल ने प्रारूप दरमानों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। ईवीटीएल ने बताया है कि दरमान स्वतंत्र अभियंता समापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है।

6.2. ईवीटीएल के प्रारूप प्रस्तावित दरमान 5 खंड क्रवर करते हैं अर्थात् खंड क - दरमान/सामान्य प्रशुल्क, खंड ख - सामान्य निबंधन और शर्तें, खंड ग- ईवीटीएल टर्मिनल सूचना, खंड घ- ग्राहक पंजीकरण प्रक्रिया और खंड ङ - ईवीटीएल संपर्क सूचना। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क अनुसूची में कार्गो प्रहस्तन प्रभार, भंडारण प्रभार और विविध प्रभारों के प्रस्तावित सूचकांकित प्रशुल्क के अतिरिक्त, ईवीटीएल ने बोलडर/विदेशी सामग्री के लिए ग्राहकों से दंड/कर, रेलवे वैगन विलम्बन शुल्क के लिए दंड/कर तथा ग्राहकों को आरोप्य कारणों के लिए सिस्टम क्षति प्रभारों के लिए प्रशुल्क भी शामिल किये हैं।

6.3. यह भी देखा जाता है कि ईवीटीएल द्वारा भेजे गए प्रारूप प्रस्तावित दरमान विभिन्न खंडों, परिभाषाओं, निबंधनों एवं शर्तों, जो प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित नहीं हैं, और इस प्राधिकरण के 29 नवंबर, 2010 के आदेश में अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क का भाग नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, ईवीटीएल द्वारा ग्राहकों से बोल्डर्स/विदेशी सामग्री के लिए ग्राहकों से दंड/उपकर और रेलवे वाहन विलम्बन शुल्क के लिए दंड/कर तथा ग्राहकों को आरोप्य कारणों के लिए सिस्टम क्षति प्रभारों के लिए प्रशुल्क भी शामिल किये हैं वीपीटी द्वारा प्रस्तावित और नवंबर 2010 के इस प्राधिकरण के आदेश में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क में नहीं पाये जाते हैं।

7.1. तत्पश्चात्, ईवीटीएल ने 16 मार्च, 2018 के अपने ई-मेल के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 2010 के आदेश द्वारा अनुमोदित दरमान के अनुरूप सूचकांकित प्रशुल्क निकालने के लिए लागू सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् संशोधित प्रस्तावित प्रारूप दरमानों की प्रति भेजी। ईवीटीएल द्वारा किये गये मुख्य निवेदन इस प्रकार है:-

- (i) 29 नवंबर, 2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा पहले अनुमोदित प्रपत्र में प्रारूप दरमान प्रस्तुत है। ईवीटीएल ने प्रारूप दरमान को अनुमोदित करने और उन्हें अधिसूचित करने का अनुरोध किया ताकि ईवीटीएल अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई कर सके।
- (ii) जहां तक स्वतंत्र अभियंता प्रमाणपत्र का संबंध है, ईवीटीएल ने पुनः दोहराया है कि स्वतंत्र अभियंता द्वारा मार्च, 2018 माह के दौरान एकीकृत जांच की जायेगी, उसके पश्चात् समापन प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और प्राप्त होते ही उसे आपके साथ साझा किया जायेगा।

7.2. ईवीटीएल ने 02 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र के द्वारा स्वतंत्र अभियंता, मैसर्स मेकन लिमिटेड, द्वारा 31 मार्च, 2018 को जारी अंतरिम समापन प्रमाण-पत्र की प्रति भेजी है। स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी अंतरिम समापन प्रमाण-पत्र बताता है कि चरण-1 का निर्माण कार्य अधूरा है और/अथवा अपूर्ण है और अंतरिम प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न पंच लिस्ट में कमियां दर्शायी गई हैं और कि सुग्राही सहमत है और स्वीकार करता है कि वह करार में निर्धारित समय और ढंग के अनुसार ऐसे सारे निर्माण कार्य पूरे और/अथवा सुधार कर लेगा। अंतरिम प्रमाण-पत्र में स्वतंत्र अभियंता ऐसे अपूर्ण कार्य की किस्म और सीमा के बारे में संतुष्ट है कि उसके समापन के अभाव में परियोजना के चरण-1 के वाणिज्यिक प्रचालनों को रोकना बुद्धिमानी नहीं है। स्वतंत्र अभियंता ने यह प्रमाणित किया है कि परियोजना के चरण-1 को उसके प्रयोक्ताओं की वाणिज्यिक सेवा में सुरक्षित और विश्वसता पूर्वक लगाया जा सकता है और करार के निबंधनों के संदर्भ में परियोजना के चरण-1 को 31 मार्च, 2018 को वाणिज्यिक परिचालन में प्रवेश के लिए अंतरिम रूप से योग्य घोषित किया जाता है।

8. मामले का संसाधन ईवीटीएल के 16 मार्च, 2018 के ई-मेल द्वारा भेजे गए अंतिम संशोधित प्रारूप दरमानों और ईवीटीएल और वीपीटी द्वारा मामले के संसाधन के दौरान दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर किया गया है।

9.1. वीपीटी के न्यासी मंडल और ईवीटीएल के बीच 13 दिसंबर, 2013 के रियायत करार के अनुसार, वीपीटी ने ईवीटीएल को लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर वीपीटी पर वर्तमान सुविधा के उन्नयन और नई सुविधा के सृजन के लिए परियोजना सौंपी। जैसा ईवीटीएल को संबोधित 14 मई, 2015 के वीपीटी के पत्र संख्या आईएमएंडईई/एमईसीएच/ओएचसी-डब्ल्यूक्यू-1/1122 के देखा जाता है कि वीपीटी ने 14 मई 2015 से रियायत अवार्ड करने की तारीख से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की अवधि के लिए रियायत अवार्ड किया।

9.2. वीपीटी ने पहले रियायत के अवार्ड की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिए वीपीटी और ईवीटीएल के बीच हुए 13 दिसंबर, 2013 के रियायत करार की एक प्रति भेजी थी। उक्त सीए का अवलोकन करने पर यह देखा गया कि ईवीटीएल को डीबीएफओटी आधार पर अवार्ड किये गए रियायत करार वीपीटी के भीतरी हार्बर में पश्चिम क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू-1) के मशीनीकरण की परियोजना के लिए है जो प्रचालक को चरण वार प्रचालनों को आरंभ करने की अनुज्ञा देता है।

10.1. अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 को 2.9.1. के अनुसार, व्यावसायिक प्रचालन आरंभ करने से पहले, निजी प्रचालक महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 48 के अधीन यथापेक्षित अपने प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेगा और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.9.2 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जाने वाले दरमान पत्तन के लिए निर्धारित और बोली दस्तावेज़ में शामिल प्रशुल्क सीमा के अनुसार होंगे परंतु उपर्युक्त खंड 2.8 में स्पष्ट किये गए सूचकांकों के अधीन होंगे। ऐसे दरमान और शर्तों का विवरण एमपीटी अधिनियम की अपेक्षानुसार प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

10.2. 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 के अनुसार महापत्तनों पर पीपीपी परियोजनाओं की स्थापना पर प्रशुल्क कैप्स मुद्रास्फीति को सूचकांकित होती हैं परंतु 1 जनवरी 2008 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन की 60% सीमा तक ही होंगी और समंजित प्रशुल्क संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।

10.3. संदर्भित सुविधा के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के 29 नवंबर, 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के दरमानों के खंड 5 के अनुसार [अनुसूची (ii) से (v) की सामान्य टिप्पणी] 1 जनवरी 2010 और संगत वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60% की सीमा तक सूचकांकन लागू करके सुविचार में लिया गया है।

10.4. अपफ्रंट प्रशुल्क के लिए आधार वर्ष और 01 अप्रैल, 2017 से तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि कारक हमारे 30 मार्च 2017 के पत्र संख्या टीएएमपी/12/2009- विविध के द्वारा वीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को पहले ही संसूचित कर दिया गया था। संदर्भित मामले में लागू वृद्धि कारक, दरमानों के खंड 5 के साथ पठित हमारे 30 मार्च, 2017 के पत्र के अनुसार 25.67% है।

11.1. इस मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:-

- (i) इस प्राधिकरण ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए वीपीटी के भीतरी हार्बर में वेस्ट क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू-1) के मशीनीकरण के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए 29 नवंबर, 2010 को आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी पारित किया था जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग-3, खंड-4) में 30 दिसंबर 2010 के राजपत्र संख्या 347 में अधिसूचित किया गया था।
- (ii) बाहरी हार्बर पर वर्तमान मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के उन्नयन और डीबीएफओटी आधार पर लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए वीपीटी की वेस्ट-क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू-1) बर्थ पर नई लौह अयस्क मशीनीकृत प्रहस्तन सुविधा का सृजन करने के लिए वीपीटी ने एसआर विज़ाग टर्मिनल लिमिटेड (ईवीटीएल) को परियोजना अवार्ड की और 13 दिसंबर 2013 को ईवीटीएल के साथ एक रियायत करार किया जो 14 मई 2015 से, रियायत अवार्ड करने की तारीख, 30 वर्ष की अवधि के लिए है।
- (iii) जैसा पहले बताया गया है, अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 को 2.9.1. के अनुसार, व्यावसायिक प्रचालन आरंभ करने से पहले, निजी प्रचालक अपने प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेगा। तदनुसार, ईवीटीएल ने इस अनुरोध के साथ इस प्राधिकरण को संपर्क किया है कि प्राधिकरण प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत यथाअपेक्षित उसके नाम से दरमानों को अधिसूचित करे।  
परियोजना के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी अंतरिक प्रमाण-पत्र में बताया है कि परियोजना का चरण-1 31 मार्च, 2018 को वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए अंतरिम रूप से योग्य घोषित किया जाता है।
- (iv) मामले का विशेषण आरंभ करने से पूर्व, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जुलाई, 2010 में वीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के अंतर्गत डीबीएफओटी आधार पर विशाखापट्टणम पत्तन के भीतरी हार्बर में वेस्ट क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू-1) स्थित मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए था।  
तदनुसार, इस प्राधिकरण ने वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर, 29 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा डीबीएफओटी आधार पर विशाखापट्टणम पत्तन के भीतरी हार्बर में वेस्ट क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू-1) पर मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधाओं के अपफ्रंट प्रशुल्क अनुमोदित किये थे।



तत्पश्चात्, वीपीटी ने 20 नवंबर, 2011 के अपने पत्र के द्वारा बाह्य हार्बर में विद्यमान सुविधाओं के मशीनीकृत उन्नयन के लिए और भीतरी हार्बर में नई सुविधाओं के सृजन के लिए यह कहते हुए चरण वार प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव दायर किया कि बाह्य और भीतरी हार्बर पर मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन की संकल्पित सुविधाएं समान हैं। 18 नवंबर, 2011 के अपने पत्र में वीपीटी ने चरण वार अपफ्रंट प्रशुल्क चाहा है और बाहरी हार्बर पर विद्यमान सुविधा के चालू करने के पश्चात् प्रारंभ में अंतरिम प्रशुल्क निर्धारण की मांग की और भीतरी हार्बर में डब्ल्यूक्यू-1 पर पूर्ण सुविधा के चालू हो जाने पर संयुक्त प्रशुल्क की। पत्तन ने अपने प्रस्ताव में बताया कि बाहरी हार्बर और भीतरी हार्बर दोनों में मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए संकल्पित सुविधाएं समान हैं।

अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश के खंड 2.2 के अनुसार निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क सीमाएं आगामी पांच वर्ष के दौरान समान कार्गो/सेवाओं के लिए बाद में बोली लगाये जाने वाली सभी परियोजनाओं पर लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त, अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 आरंभ में अंतरिम प्रशुल्क का निर्धारण और बाद में सुविधा के आरंभ होने के पश्चात् अंतिम प्रशुल्क निर्धारण अनुबद्ध नहीं करते। प्राधिकरण द्वारा वीपीटी को दिशानिर्देश की स्थिति बताये जाने पर, वीपीटी ने परीक्षण करने पर अपने 31 दिसंबर, 2011 के पत्र के द्वारा 20 नवंबर 2011 के अपने पत्र को वापस लेने का प्रस्ताव किया।

इस प्रकार, वीपीटी ने 29 नवंबर, 2010 के इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क के आधार पर बाहरी हार्बर पर वर्तमान मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के उन्नयन और डीबीएफओटी आधार पर लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए वीपीटी की वैस्ट-क्वे-1 (डब्ल्यूक्यू-1) बर्थ पर नई लौह अयस्क मशीनीकृत प्रहस्तन सुविधा का सृजन करने के लिए ईवीटीएल को परियोजना कार्य सौंपा। 13 दिसंबर 2013 को वीपीटी और ईवीटीपीएल के बीच हुए रियायत करार के परिशिष्ट 4, पत्तन द्वारा भेजी गई प्रति, के अनुसार परियोजना का विकास दो चरणों में होता है। चरण-1- बाहरी हार्बर पर विद्यमान मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा का उन्नयन करना और चरण-II भीतरी हार्बर की डब्ल्यूक्यू-1 बर्थ पर लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए नई मशीनीकृत सुविधा का सृजन करने के हैं।

ईवीटीएल ने परियोजना के चरण-1 का कार्य सफलापूर्वक समाप्त हो जाने पर प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.9.1 को देखते हुए अपने नाम से दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण से संपर्क किया है। चूंकि ईवीटीएल द्वारा उनके द्वारा विकसित चरण-1 के लिए सूचकांकित प्रशुल्क की अधिसूचना चाही है, वीपीटी को, रियायतकर्ता पत्तन होने के नाते, अनुरोध किया गया कि वह दरमानों में उपयुक्त घटौती के प्रस्ताव पर सुविचार करे ताकि यह प्राधिकरण चरण-1 के लिए दरमान अधिसूचित कर सके।

इस संबंध में, वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रस्ताव में विकास के लिए संकल्पित सुविधाएं, बाहरी हार्बर चरण-1 और भीतरी हार्बर (चरण-2) समान उपस्करों के साथ मशीनीकृत सुविधाएं हैं जैसे टिवन वैगन टिप्पलर, स्टैकर-सह-रीक्लेमर, शिप लोडर, बेल्ट कन्वेयर पे लोडर आदि जो वीपीटी के प्रस्ताव में दी गई हैं, जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा 29/11/2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा प्रशुल्क अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार, मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के लिए अधिसूचित वही प्रशुल्क, दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.2 के अनुपालन में, वर्तमान परियोजना के लिए भी अपनाया गया है, क्योंकि संकल्पित कार्गो और सेवा वीपीटी के प्रस्ताव के समरूप हैं जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा 29/11/2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा प्रशुल्क अधिसूचित किया गया था और बोली लगाई है।

वीपीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी हार्बर (चरण-1) में सुविधा का स्कोप वर्तमान सुविधा को उन्नयन करने का है जिसमें टिवन टिप्पलर, थर्ड टिप्पलर, रिसीविंग कन्वेयर स्टैकर, भंडारण यार्ड, बकट व्हील रीक्लेमर, शिपिंग कन्वेयर और शिपलोडर शामिल है, जो नवंबर, 2010 के आरंभ में लौह अयस्क सुविधा के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण चाहने के इसके प्रस्ताव में क्रवर किये गए थे। उक्त स्थिति को देखते हुए वीपीटी ने यह कहा जाता है कि 29.11.2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा

अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क को वर्तमान परियोजना के बाहरी हार्बर (चरण-1) में अपनाया जाना यथोचित और युक्तिसंगत है और किसी घटौती की जरूरत नहीं है। इसलिए, सुग्राही द्वारा अनिवार्य अपेक्षाओं के पूरा करने पर बाहरी हार्बर सुविधा (चरण-1) के लिए दरमानों को अधिसूचित करने पर सुविचार करने का अनुरोध किया जाता है। वीपीटी द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण पर विश्वास किया जाता है।

अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.9.1. के अनुसार, व्यावसायिक प्रचालन आरंभ करने से पहले, निजी प्रचालक, अपने प्रचालनों पर लागू अधिकतम दरों वाले दरमान की अधिसूचना के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेगा। तदनुसार ईवीटीएल ने खंड 2.9.1. द्वारा यथा अपेक्षित दरमानों की अधिसूचना के लिए इस प्राधिकरण को संपर्क किया है। यह प्राधिकरण भारत के राजपत्र में दरमानों की अधिसूचित करने के बाह्य है जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 का खंड 2.9.2. अधिदेश देता है।

पत्तन स्पष्टीकरण पर विश्वास करते वीओटी प्रचालक के नाम में दरमानों की अधिसूचना के मामले में ईवीटीएल द्वारा 16 मार्च 2018 के ई-मेल द्वारा भेजे गए अंतिम संशोधित प्रारूप दरमानों और मामले के संसाधन के दौरान ईवीटीएल तथा वीपीटी द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण/सूचना के आधार पर मामले का संसाधन किया जाता है।

ईवीटीएल परियोजना के चरण-1 के दरमानों की अधिसूचना चाहता है। परियोजना का चरण-वार विकास पत्तन और ईवीटीएल के बीच हुए सीए से प्रवाहित हुआ है। तथापि वीपीटी द्वारा ईवीटीएल को सौंपी गई परियोजना, जो मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा है, नवंबर 2010 में इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क को सुविचार करने के पश्चात् आमंत्रित बोली के आधार पर अवार्ड की गई थी। पत्तनने निरपेक्ष रूप से यह बताया है कि, बाहरी हार्बर (चरण-I) और भीतरी हार्बर (चरण-II) दोनों में विकसित की जाने के लिए संकल्पित सुविधाएं समान उपस्करों के साथ मशीनीकृत सुविधाएं हैं। इसलिए, ईवीटीएल के नाम में सूचकांकित दरमान अधिसूचित किये जाते हैं जो नवंबर 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के आधार पर वीपीटी में मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के लिये ईवीटीएल को अवार्ड की गई है और न कि दरमानों की चरण-वार अधिसूचना जैसा ईवीटीएल ने चाहा है।

- (v) ईवीटीएल और वीपीटी दोनों को स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी समापन प्रमाण-पत्र की प्रति भेजने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात् ईवीटीएल ने स्वतंत्र अभियंता के अंतरिम समापन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की।

यह प्राधिकरण स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी अंतरिम प्रमाण-पत्र पर विश्वास करता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि परियोजना का चरण-I 31 मार्च, 2018 से वाणिज्यिक प्रचालन में प्रवेश के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और सुयोग्य है।

ईवीटीएल को अनुमोदित दरमान समय पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, कि उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए वह दरमानों की उगाही कर सके, इस समय उसके नाम में दरमानों की अधिसूचना के लिए ईवीटीएल का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सूचकांकित दरमान उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको परियोजना की वाणिज्यिक सेवाएं उसके प्रयोक्ताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय तौर पर उपलब्ध करायी जायेंगी और कि परियोजना समापन प्रमाण-पत्र के अनुसार वाणिज्य प्रचालनों में प्रवेश के लिए योग्य घोषित की जायेगी अर्थात् 31 मार्च, 2018 ईवीटीएल और वीपीटी के स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी अंतिम समापन प्रमाण-पत्र की प्रति उसके प्राप्त होने पर तत्काल प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

- (vi) प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.9.2. के अनुसार, खंड 2.9.1. के अनुसार निजी प्रचालक के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जाने वाले दरमान पत्तन के लिए निर्धारण और बोली दस्तावेजों में शामिल प्रशुल्क सीमा के अनुसार होंगे और 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 में अनुबद्ध सूचकांकन के अधीन होंगे। 2008 के दिशानिर्देशों के खंड 2.8 अनुबद्ध करता है कि प्रशुल्क सीमाएं 1 जनवरी, 2008 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति के प्रति सूचकांकित किये जायेंगे।

वीपीटी आई ईवीटीएल के बीच हुए रियायत करार (सीए) का खंड 8.1 बाहरी हार्बर पर विद्यमान सुविधा के उन्नयन और भीतरी हार्बर पर मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन के लिए नई सुविधा के सृजन की पीपीपी परियोजना के लिए प्रशुल्क की उगाही को शासित करता है। सीए के खंड 8.1 के अनुसार, ग्राही यानी ईवीटीएल, प्रशुल्क अधिसूचना के अनुसार परियोजना सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रयोक्ताओं से प्रशुल्क की वसूली करने का पात्र होगा जिसका उद्धरण परिशिष्ट 12 में दिया गया है। सीए के साथ संलग्न परिशिष्ट 12 मद ख में इस प्राधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क का ब्यौरा दिया गया है और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान का सार उक्त परिशिष्ट 12 में संलग्न है।

- (vii) संदर्भित सुविधा के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के 29 नवंबर, 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के दरमानों के खंड 5 के अनुसार [अनुसूची (ii) से (v) की सामान्य टिप्पणी] 1 जनवरी 2010 ओर संगत वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60% की सीमा तक सूचकांकन लागू करके सुविचार में लिया गया है।

अपफ्रंट प्रशुल्क के लिए आधार वर्ष और 01 अप्रैल, 2017 से तुलनात्मक वार्षिक वृद्धि कारक हमारे 30 मार्च 2017 के पत्र संख्या टीएएमपी/12/2009- विविध के द्वारा वीपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को पहले ही संसूचित कर दिया गया था।

दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.8 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, 29 नवंबर, 2010 के आदेश के द्वारा निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में, यह विचारणीय है कि ईवीटीएल ने अपने प्रारूप प्रस्तावित दरमान दायर करते समय जनवरी 2010 के आधार वर्ष के आधार अपफ्रंट प्रशुल्क पर 25.67% का वृद्धि कारक लागू किया था। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हाल ही में 22 मार्च, 2018 के पत्र के द्वारा इस प्राधिकरण ने जनवरी, 2008, जनवरी 2009, जनवरी 2010, जनवरी 2011 और जनवरी 2012 के आधार वर्ष के साथ वर्ष 2018-19 में लागू किये जाने वाले सूचकांकन कारक की घोषणा की है। इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018-19 घोषित वृद्धि आधार वर्ष जनवरी 2010 की तुलना में जनवरी 2018 के लिए लागू वार्षिक वृद्धि कारक 25.67% ही है। अतः ईवीटीएल द्वारा दरमान निकालने के लिए लागू किया गया वार्षिक वृद्धि कारक सही पाया गया है।

- (viii) ईवीटीएल द्वारा दायर प्रारूप दरमानों से देखा जाता है कि नवंबर 2010 के आदेश के द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क मर्दे प्रयोज्य वृद्धि कारक के लागू करने को ध्यान में रख कर परिवर्तनाधीन हैं। बाद के वर्षों के लिए भी, डब्ल्यूपीआई के 60% की सीमा तक सूचकांकन 29 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी के द्वारा अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में 01 जनवरी 2010 और संबंधित वर्ष की 01 जनवरी के बीच होने वाले परिवर्तन के संदर्भ से होने चाहिए न कि अनुमोदित किये जाने वाले सूचकांकित दरमानों के संदर्भ से। 29 नवंबर 2010 के आदेश में अनुमोदित सामान्य टिप्पणी अनुसूची (2) से (4) की सामान्य टिप्पणी का बनाये रखने के ईवीटीएल के प्रस्ताव को इसलिए, इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाता है। यह उन अन्य बीओटी प्रचालकों के दरमानों में किये गए निर्धारणों के अनुरूप है जिनके प्रशुल्क निर्धारण 2008 के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं और जिन्होंने अपने प्रचालन आरंभ पर दिये हैं। यह सुविचार करते हुए कि नवंबर 2010 के आदेश में एक सामान्य टिप्पणी निर्धारित की गई है और इस पर भी विचार करते हुए कि एक सामान्य टिप्पणी अन्य महापत्तन न्यासों की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में निर्धारित की जाती है, अतः अनुसूची (2) व (4) की निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी को वीपीटी के 29 नवंबर, 2010 के आदेश और 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा शासित अन्य बीओटी प्रचालकों के दरमानों के अनुरूप ई वीटीएल के लिए अनुमोदित किये जाने वाले दरमानों की अनुसूची 5 में अंतर्विष्ट किया जाता है।

**“5. उपर्युक्त अनुसूची (2) से (4) पर सामान्य टिप्पणी:**

एसआर विजाग टर्मिनल लिमिटेड के दरमानों में निर्धारित टैरिफ कैप्स में इस प्राधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क और 1 जनवरी 2010 और संगत वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60% की सीमा तक सूचकांकन लागू करके सुविचार में लिया गया है। बाद के वर्षों के लिए भी 29.11.2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क को 1 जनवरी 2010 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच उत्पन्न थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) होने वाली भिन्नता के केवल 60% तक मुद्रास्फीति को सूचीबद्ध करेगा। टैरिफ कैप्स का इस प्रकार स्वतः समायोजन प्रति वर्ष किया जायेगा और समायोजित टैरिफ कैप्स संबंधित वर्ष की पहली अप्रैल से लागू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगा।”

(ix) 29 नवंबर, 2010 के आदेश में यथा अनुमोदित दरमानों की दरों को शासित करने वाली अन्य सभी परिभाषाएं और सोपाधिकताओं को बनाये रखा जाता है, सिवाए निम्नलिखित के:

(क) 29 नवंबर, 2010 के आदेश के दरमानों से यह देखा जाता है कि विदेशगामी पोत और तटीय पोत की परिभाषाएं निर्धारित नहीं की गई हैं। अब ईवीटीएल विदेशगामी पोत और तटीय पोत की परिभाषाओं को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया है। इस बात पर सुविचार करते हुए कि “विदेशगामी पोत” और “तटीय पोत” की परिभाषाओं को अन्य महापत्तन न्यासों और वीपीटी के अन्य अपफ्रंट प्रशुल्क आदेशों में भी निर्धारित किया जाता है और यह मान्य करते हुए कि ये ईवीटीएल द्वारा दरमानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक हैं, “विदेशगामी पोत” और “तटीय पोत” की परिभाषाओं को ईवीटीएल के नाम से अधिसूचित दरमान में निर्धारित किया जाता है, सिवा निम्न पैरा में स्पष्ट किये गए आशोधन के:

भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 11 नवंबर, 2014 के अपने पत्र संख्या पीटी-11033/51/2014-पीटी के अंतर्गत महापत्तनों पर तटीय पोतों की प्राथमिकता बर्थिंग संबंधी दिशानिर्देशों की एक प्रति भेजी है जिसे इस प्राधिकरण के 4 सितंबर, 2014 के पत्र संख्या पीटी-11033/51/2014-पीटी के द्वारा जारी किया गया। तदनुसार इस प्राधिकरण ने 28 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/52/2014-सामान्य के द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी महापत्तन न्यासों के वर्तमान दरमानों में निर्धारित “तटीय पोत” की परिभाषा के प्रतिस्थापन को अनुमोदित किया, जो इस प्रकार है:-

“**तटीय पोत**” का अर्थ पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।”

इसलिए, ईवीटीएल द्वारा प्रस्तावित तटीय पोत की परिभाषा को तटीय पोत की उपरोक्त परिभाषा के अनुरूप “पोत परिवहन महानिदेशक” शब्द जोड़ने हुए हल्का या आशोधित किया जाता है।

“विदेशगामी पोत” की परिभाषा अन्य महापत्तन न्यासों और अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के दरमानों में निर्धारित परिभाषा के अनुरूप है, अतः ईवीटीएल द्वारा यथाप्रस्तावित निर्धारित की जाती है।

(ख) ईवीटीएल द्वारा प्रस्तावित अन्य सभी शर्तें 29 नवंबर, 2010 के आदेश के अनुसार हैं और इसलिए निर्धारित की जाती हैं।

(x) दिशानिर्देश 2008 के खंड 3.8.5 के अनुसार यदि दरमानों और शर्तों के विवरण के स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या करने का कोई प्रश्न उठता है तो मामला प्राधिकरण को भेजा जायेगा और इस संबंध में उसका निर्णय प्रचालक पर बाध्यकारी होगा।

- (xi) ईवीटीएल से कम से कम बोली दस्तावेजों/रियायत करार में दिये गए निष्पादन मानकों/मानदंडों के निष्पादन की प्रत्याशा की जाती है। ईवीटीएल के वास्तविक निष्पादन की निगरानी इस प्राधिकरण द्वारा रखी जायेगी। यदि सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोपों की जांच कर सकता है और अपने निष्कर्षों को वीपीटी को भेजेगा। यदि ईवीटीएल के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी होगी तो वीपीटी रियायत करार के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करेगा।
- (xii) टर्मिनल पर वाणिज्यिक प्रचालक के दौरान ईवीटीएल को यह निदेश दिया जाता है कि वह प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर, वीपीटी के माध्यम से इस प्राधिकरण को पिछले तीन महीनों के दौरान वास्तविक और वित्तीय निष्पादन प्राप्त करने के संबंध में एक रिपोर्ट भेजेगा।

11.2. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वीपीटी में डीबीएफओटी आधार पर ईवीटी एल द्वारा मशीनीकृत लौह अयस्क प्रहस्तन सुविधा के लिए एसआर विज्ञाग टर्मिनल लिमिटेड के नाम से दरमानों की अधिसूचना को अनुमोदित करता है जैसा अनुलग्नक में संलग्न हैं।

11.3. ईवीटीएल के लिए अधिसूचित दरमान उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको परियोजना की वाणिज्यिक सेवाएं उसके प्रयोक्ताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय तौर पर उपलब्ध करायी जायेंगी और कि परियोजना स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी अंतरिम प्रमाण-पत्र के अनुसार वाणिज्य प्रचालनों में प्रवेश के लिए योग्य घोषित की जायेगी अर्थात् 31 मार्च, 2018।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./34/18]

#### अनुलग्नक

#### **एसआर विज्ञाग टर्मिनल लिमिटेड लोहा अयस्क की यांत्रिक प्रहस्तन के लिए प्रशुल्क अनुसूची**

#### **1.1. परिभाषाएं**

इस दरमान में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होने पर, निम्न परिभाषाएं लागू होंगी:

- (i) 'दिन' का अर्थ किसी दिन के प्रातः 6.00 बजे से आरंभ होकर अगले दिन की प्रातः 6.00 बजे समाप्त अवधि से है।
- (ii) 'तटीय पोत' का अर्थ पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (iii) 'विदेशगामी पोत' का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।

#### **1.2. सामान्य निबंधन और शर्तें**

##### **(i) विलंबित भुगतान/ प्रतिदाय पर ब्याज:**

- (क) उपभोक्ता इस दरमान के तहत विलंबित भुगतान पर दंडित ब्याज का भुगतान करेगा। इसी प्रकार टर्मिनल प्रचालक विलंबित प्रतिदाय पर दंडित ब्याज का भुगतान करेगा।
- (ख) दंडित ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर से 2% अधिक होगी।
- (ग) प्रतिदाय के लिए विलंब सेवा पूरी होने के दिन से **20** दिन गिने जायेंगे अथवा उपभोक्ता से अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो।
- (घ) उपभोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब टर्मिनल प्रचालक द्वारा दिये गए बिल की तिथि के **10** दिन बाद से गिना जायेगा। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां, सेवा से पूर्व भुगतान करना होता है और- दरमान में दी गई शर्त के अनुसार शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होता है।

- (ii) अन्यथा उल्लिखित न होने पर किसी एकल मद की प्रमात्रा या क्षमता के कुल भार या परिणाम का गणन करते समय 0.5 तक के भाग को 0.5 यूनिट के रूप में लिया जाए एवं 0.5 से अधिक के भाग को एक यूनिट समझा जाए।
- (iii) बिल के कुल जमा में गणना किये गये सभी शुल्क अगले रूपये में पूर्णांकित किये जायेंगे।
- (iv) (क) दरमान में वर्णित दर अधिकतम इसी प्रकार छूट और कटौती निम्न हैं। टर्मिनल प्रचालक, यदि वे चाहें निम्न दर प्रभारित कर सकते हैं और/ अथवा अधिक छूट और कटौती दे सकते हैं।  
 (ख) टर्मिनल प्रचालक सोपाधिकताएं यदि वे ऐसा चाहें- दरमान में वर्णित दरों के प्रचालन को शासित करने वाली वर्णित सोपाधिकताओं को तर्कसंगत बना सकता है यदि ऐसी तार्किकता उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दर में राहत देती है और दरमान में वर्णित यूनिट दर अधिकतम दर को पार नहीं करती।  
 (ग) टर्मिनल प्रचालक को इस प्रकार की निम्न दर और/या इस प्रकार की दरों के प्रचालन को शासित करने वाली शर्तों की तार्किकता को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करना चाहिए बशर्ते कि निर्धारित नई दरें प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक न हो।
- (v) उपभोक्ता विलंब के लिए तर्कसंगत से अधिक प्रभारों का भुगतान टर्मिनल प्रचालक को नहीं करेगा।

## 2. कार्गो प्रहस्तन प्रभार:-

क्र.सं.	वस्तु	यूनिट	दर रूपयों में
(क)	लोहा अयस्क	प्रति मी. टन	139.08

### टिप्पणी:

उपर्युक्त प्रहस्तन प्रभार, वैगन से उतराई सुविधाओं द्वारा डम्पर हाऊस में माल की उतराई और भंडारण स्थल पर उसके स्थानांतरण, 15 दिन की निःशुल्क अवधि तक स्टैक यार्ड में भंडारित करना, स्टैक यार्ड से वापिस लाना पोत पर चढ़ाना, आदि के लिए संयुक्त प्रभार है। घाट शुल्क एवं अन्य विविध सेवायें दरमान में विशेष रूप से नहीं बताई गई हैं।

## 3. भंडारण प्रभार:

15 दिन की निःशुल्क अवधि के बाद स्टैक यार्ड में रखे गये कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नानुसार होंगे।

(दर रूपये में प्रति टन, प्रति दिन या उसका अंश)

क्र.सं.	वस्तु	निशुल्क अवधि के बाद शेष कार्गो के लिए पहले सप्ताह की दर	शेष कार्गो के लिए दूसरे सप्ताह की दर	शेष कार्गो के लिए तीसरे सप्ताह की दर
1.	लोह अयस्क	0.80	1.61	3.22

### टिप्पणी:

- (i) 15 निःशुल्क दिन दिये जायेंगे, पोर्ट परिसर में माल की प्राप्ति की वास्तविक तिथि से निर्यात कार्गो के लिए निशुल्क अवधि शुरू होगी।
- (ii) निःशुल्क अवधि की गणना सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित छुट्टियों एवं टर्मिनल के अकार्य दिवस को छोड़कर की जायेगी।
- (iii) निर्धारित निःशुल्क अवधि के बाद कार्गो रखने पर भंडारण प्रभार टर्मिनल के अकार्य दिवसों और सीमाशुल्क अधिसूचित छुट्टियों सहित सभी दिवसों के लिए देय होगा।
- (iv) उपभोक्ता द्वारा अनुरोध करने पर जब टर्मिनल प्रचालक पर आरोप्य कारणों से टर्मिनल प्रचालक कार्गो को सुर्पुद/जहाज पर चढ़ाने की स्थिति में नहीं होता तब अवधि के लिए कार्गो पर भंडारण प्रभार उपाजित नहीं किया जायेगा।

**4. विविध प्रभार:**

लोहा अयस्क प्रहस्तन के लिए निम्न विविध प्रभार लागू हैं:

क्र.सं.	विवरण	प्रति टन या उसके अंश के लिए दर (रुपये में)
(i)	झाड़ना, धूलि दमन एवं पर्यावरण आदि विविध सेवाओं के लिए प्रभार	1.42

**5. उपर्युक्त अनुसूची (2) से (4) पर सामान्य टिप्पणी:**

एसआर विजाग टर्मिनल लिमिटेड के दरमानों में निर्धारित टैरिफ कैप्स में इस प्राधिकरण द्वारा 29 नवंबर, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क और 1 जनवरी, 2010 और संगत वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 60% की सीमा तक सूचकांकन लागू करके सुविचार में लिया गया है। बाद के वर्षों के लिए भी 29.11.2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी में अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क को 1 जनवरी, 2010 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच उत्पन्न थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में होने वाली भिन्नता के केवल 60% तक मुद्रास्फीति को सूचीबद्ध करेगा। टैरिफ कैप्स का इस प्रकार स्वतः समायोजन प्रति वर्ष किया जायेगा और समायोजित टैरिफ कैप्स संबंधित वर्ष की पहली अप्रैल से लागू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगा।

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th April, 2018

**No. TAMP/8/2018-VPT.**— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the M/s.Essar Vizag Terminals Limited for notification of its Scale of Rates for mechanised iron ore handling facility at Visakhapatnam Port Trust (VPT) through Public Private Partnership on Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT) basis as in the Order appended hereto

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No. TAMP/8/2018-VPT

M/s. Essar Vizag Terminals Limited

...

Applicant

**QUORUM:**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on 5<sup>th</sup> day of April 2018)

This case relates to the proposal received from the M/s.Essar Vizag Terminals Limited (EVTL) for notification of its Scale of Rates for upgradation of the existing outer harbour mechanized facility (Phase-I) at Visakhapatnam Port Trust (VPT) for Iron Ore handling through Public Private Partnership on Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT) basis.

2. Before bringing out the submissions made by the EVTL in its proposal dated 11 January 2018, it is relevant here to mention that this Authority had passed an Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 fixing upfront tariff based on the proposal filed by the VPT under upfront tariff fixation Guidelines, 2008 for mechanized handling of iron ore at West Quay-1 (WQ1) berth in inner harbor of VPT on DBFOT basis. The said Order was notified in the Gazette of India on 30 December 2010 vide Gazette No.347.

3.1. The EVTL vide its letter dated 11 January 2018 has requested this Authority to notify Scale of Rates in its name. The main points made by EVTL are summarized below:

- (i) EVTL has taken over the Phase-I Outer Harbour Mechanized Facility from VPT through PPP on DBFOT basis w.e.f. 14 May 2015 and has achieved 98% Project completion as on 31 December 2017. In the present scenario, EVTL expects to complete the Phase-I Project by 28 February 2018.
- (ii) In the above context, EVTL draws attention to the applicability of “revised cargo-handling tariff”, on successful completion of Phase-I Project, in-line with the Guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Port Trusts, 2008.
- (iii) Tariff caps for mechanized handling of iron ore at VPT have been fixed in November 2010 vide tariff Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010, which is as follows:

(a) Cargo handling charges – ₹110.67 per metric tonne

(b) Storage charges beyond 15 days of free period (in ₹ per tonne per day or part thereof)

Rate for 1 <sup>st</sup> Week for the balance cargo remaining after the free period	Rate for second week for the balance cargo	Rate for third week onwards for the balance cargo
0.64	1.28	2.56

(c) Miscellaneous charges – ₹1.13 per tonne or part thereof

- (iv) With reference to TAMP Circular towards indexation factor to arrive at the indexed tariff caps for upfront tariff cases fixed under Upfront Tariff Guidelines 2008 for the FY 2017-18, “revised cargo handling tariff” is as shown below, considering the escalation factor of 25.67% for FY 2017-18, from the date of project completion.

(a) Cargo handling charges – ₹139.08 per metric tonne

(b) Storage charges (in ₹ per tonne per day or part thereof)

Rate for 1 <sup>st</sup> Week for the balance cargo remaining after the free period	Rate for second week for the balance cargo	Rate for third week onwards for the balance cargo
<b>0.84</b>	<b>1.61</b>	<b>3.22</b>

(c) Miscellaneous charges – ₹1.42 per tonne or part thereof

[The Base year prescribed in the general note to the SOR for applying 60% of the WPI escalation is 01 January 2010].

3.2. The EVTL has furnished the Tariff Appendix of the “Concession Agreement” (CA) between VPT and EVTL for ready reference and has requested to duly review the revision in SOR and to notify the same as required by the Major Port Trusts Act.

4.1. The proposal of EVTL is for notification of SOR in its name in view of clause 2.9.1. of the tariff guidelines of 2008 on successful completion of Phase-I Project i.e. upgradation of existing mechanised iron ore handling facility of Outer harbor.

4.2. On initial scrutiny of the proposal, it was noticed that the proposal of EVTL for notification of its Scale of Rates is not accompanied with the following documents:

- (i) Proposed Scale of Rates (SOR) complete in all respects along with the conditionalities.
- (ii) A copy of the completion certificate issued by the Independent Engineer.



4.3. Accordingly, the EVTL was requested, vide our letter dated 02 February 2018 to furnish the requisite documents/information immediately. The EVTL was also requested to forward a copy of proposed SOR to VPT also for its comments. This was followed by reminders dated 28 February 2018 and 09 March 2018.

5.1. The VPT, being the Concessionaire Port, was requested vide our letter dated 02 February 2018 to furnish information/ clarification on a few points. The VPT was also requested to furnish a copy of the completion certificate issued by the Independent Engineer and furnish comments on receipt of the proposed draft SOR alongwith conditionalities from EVTL at the earliest.

5.2. With reference to our letter dated 02 February 2018 and reminder dated 28 February 2018, the VPT has furnished its response vide its letter dated 07 March 2018. A summary of the information/ clarifications / documents / comments sought by us and reply furnished by VPT is juxtaposed below:

Sl. No.	Information / clarifications sought by us	Information / clarifications of the VPT
1.	<p>The upfront tariff approved by the Authority in the Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 for mechanization of WQ-1 berth in the inner harbour of VPT for handling iron ore is for the project facility envisaged by the VPT with a total estimated Capital cost of ₹275.20 crores as can be seen from the Annex – I attached to the said Order. The EVTL has now filed proposal seeking notification of the SOR for phase I of its project. It is seen from the Concession Agreement entered between VPT and EVTPL dated 13 December 2013 that Phase I is for upgradation of existing mechanised iron ore handling facility and does not involve full fledge capital investment envisaged for this project for which the upfront tariff was sought and approved. From Appendix 4 of page 120-129 of the Concession Agreement, it is seen that most of the investment in equipment which were estimated by VPT in the Project Cost while seeking upfront tariff are envisaged to be deployed in Phase-II. The VPT, being the Concessionaire port may consider to propose suitable reduction in the SOR to enable the Authority to notify SOR for Phase-I of the project subject to production of completion certificate to be issued by the Independent Engineer.</p> <p>Incidentally, in a somewhat similar scenario, the V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) while processing a proposal for notification of the indexed upfront SOR in the name of a BOT operator governed under tariff guidelines of 2008, had itself proposed for reduction in the SOR till the completion of conveyor facility and commencement of full fledged operations by the operator.</p>	<p>(a) The project "Upgradation of the existing facility in the Outer Harbour and development of new facility in the Inner Harbour for iron ore handling" is awarded on DBFOT basis at Visakhapatnam Port Trust at an estimated cost of ₹845.41 crores to M/s.Essar Vizag Terminals Ltd., on 14 May 2015. The project development is envisaged in two phases:</p> <p>(i) Phase-I: upgradation of the existing mechanised iron ore handling facility in the Outer Harbour initially at estimated cost of ₹395.02 crores and a onetime upfront fee of ₹185.87 crores towards value of existing plant, machinery along with Civil structures to be paid by concessionaire to Concessioning Authority.</p> <p>(ii) Phase-II: Development of new facility in the inner harbour at estimated cost of ₹264.52 crores after attaining 12.5 million tonnes at Outer Harbour or 2 million tonnes at Inner Harbour whichever is earlier.</p> <p>(b) Appendix-4(D) of the Concession Agreement states that "In case, minimum throughput as detailed in clause (B) above is not achieved within three (3) years from the date of award of concession, the Additional Guarantee (as stated in Article 4.2 of the Concession Agreement) submitted by the Concessionaire as a token of commitment for commencement and execution of Phase II investment will be returned and the Concessioning Authority shall have the option to take alternative action about WQ1 berth".</p> <p>(c) Proposal for fixation of upfront tariff for the project to be developed in two phases was sent to TAMP vide VPT letter No.IRNP/Stdsl.Ore/Tariff2012 dated 20.11.2012.</p> <p>TAMP vide letters No.TAMP/77/2012-VPT dated 7.12.2012 and 31.12.2012 has stated the following:</p> <p>(i) Tariff caps for mechanised handling of iron ore at VPT have been fixed in November 2010 vide tariff Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29.11.2010 wherein the mechanised handling of</p>

	<p>iron ore was envisaged with the deployment of equipment like twin wagon tippler, stacker cum reclaimers, ship loader, belt conveyor, payloaders, etc.</p> <p>(ii) As per clause 2.2 of the guidelines for upfront tariff setting, the tariff caps prescribed would be applicable to all projects to be bid out subsequently for identical cargo/service during the next five years. In other words, the upfront tariff fixed for mechanised handling of iron ore in November 2010 will apply to all projects bid out till November 2015.</p> <p>(iii) Tariff caps for handling iron ore at Visakhapatnam port Trust (VPT) has already been fixed in 2010 and that review is to be undertaken only in 2015.</p> <p>(iv) The upfront tariff guidelines do not stipulate fixation of upfront tariff based on the stage wise development of the facility.</p> <p>(d) With reference to the information sought at point (i), it is to clarify that the facilities envisaged to be developed in the current proposal, both in the Outer Harbour (Phase-I) and in the Inner Harbour (Phase-II) are mechanised facilities with similar equipment such as wagon tipplers, stackers, reclaimers, ship loader, belt conveyor, etc., contained in the proposal of VPT for which upfront tariff was notified by TAMP vide tariff Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29.11.2010.</p> <p>(e) As such, the same tariff notified for mechanised iron ore handling facility is adopted to the current project also in compliance of clause 2.2 of the 2008 guidelines, since the envisaged cargo and service are identical to the proposal of VPT for which upfront tariff was notified by TAMP vide tariff Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29.11.2010 and bid out</p> <p>(f) It is also to clarify that the scope of the facility in the outer harbour (Phase-I) is upgradation of the existing facility which includes twin tippler, third tippler, receiving conveyors, stackers, storage yard, bucket wheel reclaimers, shipping conveyor and ship loader. A one time upfront fee of ₹185.87 crores was paid by the Concessionaire to VPT towards the value of the existing plant and machinery along with civil structural excluding land of ore handling complex made available by the Concessioning Authority, before the Date of Award of Concession. The estimated cost for upgradation of this facility was ₹395.02 crores. Thus, the total estimated cost of the mechanised facility was ₹580.89 crores in Phase-I. The capacity of the facility is estimated to be augmented from 12.5 MTPA to 16.2 MTPA.</p> <p>(g) Further, it is to clarify that Phase-I and Phase-II are independent but not inter dependent. Phase-I and Phase-II deliver the output independently. Appendix 4 (D) of the concession agreement clearly states that Phase-II development of new facility in</p>
--	---

		<p>the inner harbor at an estimated cost of ₹264.52 crores after attaining 12.5 million tonnes at outer harbor or 2 million tonnes at inner harbor, whichever is earlier. If the same is not achieved within a period of 3 years from the date of award, the additional guarantee as stated at Article 4.2 is to be returned and the Concessioning Authority shall have the option to take alternative action about WQ-1 facility.</p> <p>In view of the above, it is opined that adopting the upfront tariff notified vide tariff order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29.11.2010 to the current project in the Outer Harbour (Phase-I) is reasonable and rational and no reduction is warranted. It is, therefore, requested to consider notifying the SOR for the Outer Harbour facility (Phase-I) upon fulfilment of the mandatory requirements by the Concessionaire.</p>
2.	The VPT to furnish a copy of the completion certificate issued by the Independent Engineer in this regard.	The VPT has not responded to this point.
3.	The EVTL has not forwarded proposed draft SOR for the project. The EVTL has been requested to furnish the complete proposed draft SOR to VPT as well as to TAMP. The VPT to furnish its comments on receipt of the proposed draft SOR from EVTL at the earliest.	<p>No comments furnished by the port.</p> <p><i>[The EVTL has forwarded a copy of SOR to VPT vide its letter dated 7 March 2018 and revised SOR vide email dated 16 March 2018.]</i></p>

6.1. In response to our letter dated 02 February 2018, the EVTL has, vide its email dated 09 March 2018 forwarded a copy of proposed draft SOR along with general terms and conditions. The EVTL has also endorsed a copy of the proposed SOR to VPT. The main submissions made by the EVTL are given below:

- (i) Draft proposed Scale of Rates (SOR) is furnished covering all general terms & conditions; terminal information; customer registration procedure; and contact information. The proposed rates mentioned in section A is subject to change for Financial Year 2018-19 based on the further TAMP circular towards indexation factor. The copy of the Draft SOR is also sent to VPT for its review and comments.
- (ii)
  - (a) With regards to Independent Engineer Completion certificate, EVTL has stated that most of the project activities have been individually inspected and punch-points issued by Independent Engineer were also attended to the maximum extent. As on 28 February 2018, EVTL was able to complete 99.34% of project.
  - (b) EVTL foresees the integrated tests by Independent Engineer will be carried-out during the month of March 2018, upon which completion certificate shall be issued by Independent Engineer and the same will be shared immediately on receipt.
- (iii) In this backdrop, the EVTL has requested to review the draft SOR. The EVTL has stated that SOR shall be proposed to be applicable from the date of receipt of Independent Engineer Completion Certificate.

6.2. The draft proposed SOR by EVTL covered 5 Section viz. Section A - Scale of Rates / General Tariff, Section B - General Terms and Conditions, Section C - EVTL Terminal Information, Section D - Customer Registration Procedure and Section E - EVTL Contact Information. Further, in the tariff Schedule apart from proposing indexed tariff for cargo handling charge, storage charges and miscellaneous charges the EVTL has also included tariff for Penalties/ levies from customers for Boulders/ Foreign material, and Penalties/ Levies towards Railway wagon demurrages and system damages charges for reasons attributable to customers.

6.3. It is also seen that the draft proposed SOR forwarded by EVTL various section, definitions, terms and conditions which are not related to tariff fixation and do not form part of the upfront tariff notified by this Authority in the Order dated 29 November 2010. Further, the tariff included by the EVTL as regards Penalties/ Levies from customers for Boulders/ Foreign material, and penalties Levies towards Railway wagon demurrages and system damages charges

for reasons attributable to customers are not found to be in the Upfront tariff proposed by VPT and approved by this Authority in November 2010 Order.

7.1. Subsequently, the EVTL has, vide its email dated 16 March 2018 forwarded a copy of revised proposed draft SOR in line with the SOR approved by this Authority vide Order dated 29 November 2010 after applying applicable indexation factor to arrive at the indexed tariff. The main submissions made by the EVTL are given below:

- (i) The draft scale of rates (SOR) is furnished in the format approved earlier vide tariff order no.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010. The EVTL requests to approve the Draft SOR and notify the same so that M/s.EVTL may take necessary action at its end.
- (ii) With regard to Independent Engineer Completion Certificate, EVTL has reiterated that it expects the integrated tests by Independent Engineer will be carried-out during the month of March 18, upon which completion certificate shall be issued and the same will be shared as soon as it is issued.

7.2. The EVTL has, vide its letter dated 02 April 2018, forwarded a copy of the provisional completion certificate dated 31 March 2018 issued by the Independent Engineer, M/s.Mecon Ltd. The Provisional Completion Certificate issued by Independent Engineer states that the construction works in respect of Phase-I are found to be incomplete and / or deficient and have been specified in the Punch List appended to the Provisional Certificate, and the Concessionaire has agreed and accepted that it shall complete and / or rectify all such works in the time and manner set forth in the Agreement. The Independent Engineer in the provisional certificate is satisfied that having regard to the nature and extent of such incomplete works, it would not be prudent to withhold commercial operation of Phase – I of the project, pending completion thereof. The Independent Engineer has certified that Phase – I of the project can be safely and reliably placed in commercial service of the users thereof, and in terms of the Agreement, Phase-I of the project is provisionally declared fit for entry into commercial operation on 31 March 2018.

8. The case has been processed based on the final revised draft SOR forwarded by EVTL vide its email dated 16 March 2018 and based on information/ clarification furnished by the EVTL and VPT during the processing of the case.

9.1. As per the Concession Agreement dated 13 December 2013 between the Board of Trustees of VPT and the EVTL, the VPT has awarded the project of Upgradation of existing facility and creation of new facility at VPT for Iron Ore handling on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis to EVTL. As seen from the copy of VPT letter No.IM&EE/MECH/OHC-WQ-1/1122 dated 14 May 2015 addressed to the EVTL, the VPT has awarded the concession to EVTL with effect from 14 May 2015 for a period of 30 years commencing from the date of award of concession.

9.2. The VPT had earlier forwarded a copy of the Concession Agreement entered between VPT and EVTPL dated 13 December 2013 for a period of 30 years from the date of award of concession. On perusing the said CA, it is seen that the Concession Agreement for the project of mechanization of West Quay-1 (WQ-1) berth in the inner harbour at VPT on DBFOT awarded to EVTL, allows phase wise commencement of operations by the operator.

10.1. As per Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff, the private operator shall approach this Authority for notification of Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of MPT Act and as per Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by TAMP shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such Scale of Rates and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.

10.2. As per clause 2.8 of the guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Ports, 2008, the Tariff Caps are to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

10.3. As per clause 5 [General Note to Schedule (ii) to (v)] of the Scale of Rates of the upfront tariff Order dated 29 November 2010 fixing upfront tariff for the facility in reference, tariff caps have to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year.

10.4. The base year for the upfront tariff and the corresponding annual escalation with effect from 01 April 2017 were already communicated to all the Major Port Trusts including VPT vide our letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 30 March 2017. The escalation factor to be applied in the case in reference is 25.67% as per our letter dated 30 March 2017 read with clause 5 of the Scale of Rates.

11.1. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) This Authority has passed an Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 disposing of the proposal filed by the Visakhapatnam Port Trust (VPT) under Tariff Guidelines 2008 for fixation of upfront tariff for mechanization of West Quay-1 (WQ-1) berth in the inner harbour of VPT for handling iron ore on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis which were notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 30 December 2010 vide Gazette No.347
- (ii) The VPT has awarded the project of Upgradation of existing mechanized iron ore handling facility at outer harbour and creation of new mechanized iron ore handling facility at WQ-1 berth of VPT for Iron Ore handling on DBFOT basis to Essar Vizag Terminals Limited (EVTL) and entered into a Concession Agreement with EVTL on 13 December 2013 for a period of 30 years with effect from 14 May 2015, the date of award of concession.
- (iii) As brought out earlier, Clause 2.9.1. of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff requires the private operator to approach this Authority for notification of the Scale of Rates containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations. Accordingly, the EVTL has approached this Authority with a request to notify the Scale of Rates in its name as required under the Tariff Guidelines of 2008.

The Independent Engineer has stated in the Provisional Certificate issued for the Project that Phase-I of the project is provisionally declared fit for commercial operations on 31 March 2018.

- (iv) Before proceeding to analyse the case, it is relevant here to state that the proposal filed by the VPT in July 2010 was for fixation of upfront tariff for mechanized iron ore handling facilities at West Quay-1 (WQ-1) berth in the inner harbour of Visakhapatnam Port on DBFOT basis under the Upfront tariff guidelines of 2008 issued by the Ministry of Shipping based on the proposal filed by the VPT.

Accordingly, this Authority has, vide its Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 approved the upfront tariff for mechanized iron ore handling facilities at West Quay-1 (WQ-1) berth in the inner harbour of Visakhapatnam Port on DBFOT basis.

Subsequently, the VPT vide its letter dated 20 November 2011 had filed a proposal for seeking phase wise tariff for mechanized upgradation of existing facilities in outer harbor and creation of new facility in inner harbor stating that facilities envisaged for mechanized handling of iron ore at both outer and inner harbor are identical. In its letter dated 18 December 2011, VPT had sought upfront tariff in phases seeking interim tariff initially after commissioning of existing facility at outer harbor and combined tariff after commissioning of full fledged facility at WQ1 in inner harbor. The port had in its proposal stated that the facilities envisaged for mechanized handling of iron ore at both outer harbor and inner harbor are the same.

As per clause 2.2. of the upfront tariff guidelines, upfront tariff caps prescribed is applicable to all projects to be bid out subsequently for identical cargo/ services during the next five years. Further, the upfront tariff guidelines of 2008 do not stipulate fixation of interim tariff in the beginning and final tariff at a later point of time after commissioning of operation at the facility. The VPT, on examining the above guidelines position pointed out to VPT by TAMP, had vide its letter dated 31 December 2011 proposed to withdraw its earlier proposal dated 20 November 2011.

The VPT has, thus, based on the upfront tariff notified by this Authority vide Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 awarded the project to EVTL for upgradation of the existing facility in the Outer Harbour for mechanized iron ore handling and for development of new facility in the Inner Harbour for mechanized iron ore to EVTL on DBFOT basis. It is seen from the Appendix 4 of Concession Agreement entered between VPT and EVTL dated 13 December 2013 forwarded by the port that the development of the project is in two phases. Phase I is for Upgradation of existing mechanised iron ore handling facility of Outer Harbour and Phase-II is for creation of mechanised facility at WQ-1 berth of Inner Harbour for handling iron ore.

The EVTL has approached this Authority for notification of SOR in its name in view of clause 2.9.1. of the tariff guidelines of 2008 on successful completion of Phase-I Project. Since the notification of indexed tariff sought by the EVTL was for phase I of the project developed by them, the VPT, being

the Concessionaire port was requested that port may consider to propose suitable reduction in the SOR to enable this Authority to notify SOR for Phase-I.

In this regard, the VPT has clarified that facilities envisaged to be developed in the current proposal, both in the Outer Harbour (Phase-I) and in the Inner Harbour (Phase-II) are mechanised facilities with similar equipment such as wagon tipplers, stackers, reclaimers, ship loader, belt conveyor, etc., contained in the proposal of VPT for which upfront tariff was notified by TAMP vide tariff Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010. As such, the same tariff notified for mechanised iron ore handling facility is adopted to the current project also in compliance of Clause 2.2 of the 2008 guidelines, since the envisaged cargo and services are identical to the proposal of VPT for which upfront tariff was notified by TAMP vide tariff Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 and bid out. The VPT has also clarified that the scope of the facility in the outer harbour (Phase-I) is upgradation of the existing facility which includes twin tippler, third tippler, receiving conveyors, stackers, storage yard, bucket wheel reclaimers, shipping conveyor and ship loader which were covered in its proposal seeking upfront tariff fixation for iron ore facility in November 2010 Order. In view of the above position the VPT has opined that adopting the upfront tariff notified vide tariff order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 to the current project in the Outer Harbour (Phase-I) is reasonable and rational and no reduction is warranted. The clarification furnished by the VPT is relied upon.

As per clause 2.9.1 of the upfront tariff guidelines of 2008, the operator before commencement of commercial operation needs to approach this Authority for notification of Scale of Rates as required under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963. Accordingly, the EVTL has approached this Authority for notification of the Scale of Rates as required by clause 2.9.1. This Authority is bound to notify the Scale of Rates in the Gazette of India as mandated by the clause 2.9.2 of the Tariff Guidelines of 2008.

Relying on the clarification of the port, the case has been processed for notification of the Scale of Rates in the name of BOT operator based on the final revised draft SOR forwarded by EVTL vide its email dated 16 March 2018 and based on information/ clarification furnished by the EVTL and VPT during the processing of the case.

The EVTL has sought notification of SOR for phase I of the project. The phase wise development of the project flows from the C.A. signed between the port and the EVTL. However, the project awarded by the VPT to EVTL is based on bids invited by the port taking into consideration the upfront tariff notified by this Authority in November 2010 which is for the mechanized handling of iron ore facility. The port has categorically stated that facilities envisaged to be developed both in the Outer Harbour (Phase-I) and in the Inner Harbour (Phase-II) are mechanised facilities with similar equipment. Therefore, the indexed SOR in the name of the EVTL is notified for the mechanized handling of iron ore facility at VPT awarded to EVTL based on the upfront tariff Order of November 2010 Order and not for phase wise notification of SOR as sought by the EVTL.

- (v) Both the EVTL and the VPT were requested to furnish copy of completion certificate issued by the Independent Engineer. The VPT has not responded. The EVTL has confirmed that most of the project activities have been individually inspected and punch-points issued by Independent Engineer were also attended to the maximum extent. The EVTL has reported that 99.34% of project is completed as on 28 February 2018. Subsequently, the EVTL has furnished a copy of the Provisional completion certificate of the Independent Engineer.

This Authority relies on the provisional certificate issued by the Independent Engineer certifying that Phase I of the project is safe and reliable and fit for entry into commercial operations from 31 March 2018.

In order to make the approved SOR available to EVTL in time so that it can levy the SOR for the services rendered by it, the proposal of EVTL for notification of the Scale of Rates in its name at this juncture is approved. The indexed SOR approved by this Authority will come into force from the date the Project can be safely and reliably placed in commercial service of the users thereof, and that the Project has been declared fit for entry into commercial operation as per the Completion Certificate i.e. from 31 March 2018. The EVTL and VPT are advised to share the copy of the final Completion Certificate issued by the Independent Engineer immediately on its receipt.

- (vi) As per Clause 2.9.2. of the Tariff Guidelines of 2008, the Scale of Rates to be framed by this Authority for the private operator as per Clause 2.9.1 should be in line with the tariff caps prescribed for the Port and included in the bid document, subject to indexation as stipulated in clause 2.8 of 2008 guidelines. Clause 2.8 of the 2008 guidelines stipulates that tariff caps will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in WPI occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year.

Article 8.1 of the Concession Agreement (C.A.) entered between the VPT and EVTL governs levy of the tariff for the PPP Project of Upgradation of existing facility at outer harbor and creation of new facility at VPT at inner harbor for mechanized Iron Ore handling. As per Article 8.1 of the C.A., the Concessionaire i.e. EVTL shall be entitled to recover tariff from the users of the Project Facilities and Services as per the Tariff Notification, an extract of which is set out in Appendix-12. Appendix 12, Item B appended to C.A gives reference to the Notification details of the Upfront Tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 and an extract of the SOR notified by this Authority is attached to the said Appendix 12.

- (vii) As per clause 5 [General Note to Schedule (ii) to (v)] of the Scale of Rates of the upfront tariff Order dated 29 November 2010 fixing upfront tariff for the facility in reference, tariff caps have to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year.

The base year for the upfront tariff and the corresponding annual escalation with effect from 01 April 2017 were already communicated to all the Major Port Trusts including VPT vide our letter No.TAMP/12/2009-Misc. dated 30 March 2017.

With reference to the indexation of the upfront tariff fixed vide Order dated 29 November 2010 as required under Clause 2.8. of the 2008 Guidelines, it is noteworthy that the EVTL, while filing of its draft proposed SOR, has applied escalation factor at 25.67% on the base upfront tariff of the base year January 2010. It is relevant here to state that recently vide our letter dated 22 March 2018, the indexation factor to be applied for the year 2018-19 has been announced by this Authority with reference to the January 2018 with the base year of January 2008, January 2009, January 20010, January 2011 and January 2012. The escalation announced by this Authority for the year 2018-19 for base year January 2010 vis-à-vis 1 January 2018 is same at 25.67%. Thus, the annual escalation factor applied by EVTL to arrive at the SOR is found to be in order.

- (viii) It is seen from the draft SOR filed by the EVTL that the tariff items notified vide Order of November 2010 have been subjected to change in view of the application of applicable escalation factor. For the subsequent years as well, the indexation to the extent of 60% of the WPI has to be with reference to the variation occurring between 01 January 2010 as notified in the upfront tariff schedule vide Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 and 01 January of the relevant year and not with reference to the indexed Scale of Rates to be approved. The General note to Schedule (2) to (4) proposed by EVTL retaining the general note approved in the Order dated 29 November 2010 is, therefore, suitably modified clarifying this position. This is in line with the prescription made in the Scale of Rates of other BOT operators whose tariff fixation is governed under 2008 guidelines who have commenced the operations. Considering that a General Note is prescribed in the November 2010 Order and also considering that a General Note is prescribed in the upfront tariff schedule of other major port trusts, the following General note to Schedule (2) & (4) is, therefore, incorporated under Schedule 5 of the Scale of Rates to be approved for EVTL in line with the prescription in the Order dated 29 November 2010 of VPT and the Scale of Rates of the other BOT operators governed under 2008 tariff guidelines:

**“5. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (4) ABOVE:**

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of Essar Vizag Terminals Limited takes into consideration the upfront tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.”

- (ix) All other definitions and conditionalities governing the application of the rates as approved in the Scale of Rates of the Order dated 29 November 2010 are retained subject to the following:
- (a) It is seen from SOR of the Order dated 29 November 2010, definitions of Foreign going vessel and Coastal vessel was not prescribed. Now EVTL has proposed to incorporate definitions of Foreign going vessel and Coastal vessel. Considering that the definitions of “Foreign going

vessel” and “Coastal vessel” are prescribed in the upfront tariff schedule of other major port trusts and other upfront Orders of VPT as well, and recognising that these are relevant for application of the SOR by EVTL, the definition of the terms “Foreign going vessel” and “Coastal vessel” is prescribed in the SOR notified in the name of EVTL except modification explained in immediate subsequent paragraph.

The Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) under cover of its letter No.PT-11033/51/2014-PT dated 11 November 2014 has forwarded a copy of the guidelines on priority berthing of coastal vessels at Major Port issued vide letter No.PT-11033/51/2014-PT dated

4 September 2014 to this Authority. Accordingly, this Authority vide its Order No.TAMP/52/2014-Genl. dated 28 November 2014 has, *inter alia*, approved the replacement of definition of ‘Coastal Vessel’ prescribed in the existing SOR of all the Major Port Trusts as follows:

*“Coastal vessel” shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Director General of Shipping/ Competent Authority.*

Therefore, the definition of Coastal Vessel proposed by the EVTL has been slightly modified adding the words “Director General of Shipping” in line with the above mentioned definition of ‘Coastal Vessel’.

The definition of "Foreign-going vessel" is found to be in line with the definition uniformly prescribed in the SOR of other Major Ports and upfront tariff Order and hence is prescribed as proposed by EVTL.

- (b) All other conditions proposed by EVTL are as per the Order dated 29 November 2010 and hence same is prescribed.
- (x) As per clause 3.8.5 of the 2008 guidelines, if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the operator.
- (xi) The EVTL is expected to perform at least at the performance standards / norms brought out in the bid documents / Concession Agreement. The actual performance of the EVTL will be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority may enquire into such allegation and forward its findings to the VPT. If any action is to be taken against the EVTL, the VPT shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the Concession Agreement.
- (xii) During the commercial operation at the terminal, within 15 days from the end of every quarter, the EVTL is directed to submit to this Authority through the VPT a report containing the physical and financial performance during the preceding three months.

11.2. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, this Authority approves notification of Scale of Rates in the name of Essar Vizag Terminals Limited for mechanized handling of iron ore facility operated by EVTL on DBFOT basis at VPT attached as **Annex**.

11.3. The Scale of Rates notified for EVTL will come into force from the date the Project can be safely and reliably placed in commercial service of the users thereof, and that the Project has been declared fit for entry into commercial operation as per the Provisional Certificate issued by the Independent Engineer i.e. from 31 March 2018.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./34/18]

**Annex**

### **ESSAR VIZAG TERMINALS LIMITED TARIFF SCHEDULE FOR MECHANISED HANDLING OF IRON ORE**

#### **1.1. DEFINITIONS**

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i) **"Day"** shall mean the period starting from 6.00 A.M. of a day and ending at 6.00 A.M. on the next day.



- (ii) "**Coastal vessel**" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Director General of Shipping/Competent Authority.
- (iii) "**Foreign-going vessel**" shall mean any vessel other than Coastal vessel.

## 1.2. GENERAL TERMS & CONDITIONS

- (i) Interest on delayed payments / refunds.
- (a) The user shall pay penal interest on delayed payments of under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.
- (b) The rate of penal interest will be 2% above the prime lending rate of the State Bank of India.
- (c) The delay on refunds will be counted only 20 days from the day of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (d) The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the scale of rates.
- (ii) In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto and inclusive 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of above 0.5 shall be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (iii) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (iv) (a) The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if they so desire, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.
- (b) The terminal operator may also, if they so desire rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.
- (c) The terminal operator should notify the public such lower rates and / or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (v) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to terminal operator.

## 2. CARGO HANDLING CHARGES:

Sl. No.	Commodity	Unit	Rate in `
(a)	Iron Ore	Per Metric Tonne	139.08

### Note:

The handling charges prescribed above is a composite charges for unloading of cargo from wagon through unloading facilities at dumper house, transfer the same upto the point of storage, storage at the stack yard upto a free period of 15 days, reclaiming from stack yard, loading onto the ship, wharfage and all other miscellaneous services not specifically prescribed in the scale of rates.

## 3. STORAGE CHARGES:

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period of 15 days shall be as below:

(Rate in ` per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Commodity	Rate for first week for the balance cargo remaining after the free period	Rate for second week for the balance cargo	Rate for third week onwards for the balance cargo
1.	Iron ore	0.80	1.61	3.22

### Notes:

- (i) 15 free days shall be allowed. Free period for export cargo shall commence from the actual date of the receipt of goods in the Port premises.
- (ii) For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (iii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

- (iv) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.

**4. MISCELLANEOUS CHARGES:**

The following Miscellaneous charges are applicable for iron ore handled:

Sl. No.	Particulars	Rate per tonne or part thereof (in `)
(i)	Charges for all miscellaneous services such as sweeping, dust suppression and environment etc.	1.42

**5. GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (4) ABOVE:**

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of Essar Vizag Terminals Limited takes into consideration the upfront tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2010 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.